tions Act, 1961 read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965 issued by the Vice-President discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala:—

(a) The Kerala Municipal Corporations (Powers of Officers authorised to hold inquiries) Rules, 1966, published in Notification S.R.O. No. 320/66 in Kerala Gazette dated the 23rd August, 1966.

(b) The Kerala Municipal Corporations (Enforcement of Vaccination) Rules, 1966, published in Notification S.R.O. No. 333/66 in Kerala Gazette dated the 6th September, 1966.

[*Placed in Library. See* No. LT-7193/66].

12.15 hrs.

STATEMENT *RE*: FINANCE MINISTER'S VISIT TO CANADA AND U.S.A.

Mr. Speaker: Shri Sachindra Chaudhuri.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेहरबानी कर के 355 नियम देखिये।

अध्यक्ष महोदय : इस आइटम पर ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां। जब किसी वाद-विवाद के दौरान या किसी पर्याप्त कारण से कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य से सफाई जानकारी के लिए कोई सवाल पूछना चाहता है तो वह यह सवाल अध्यक्ष की मार्फत सदस्य से पूछ सकता है। श्री शचीन्द्र चौधरी विदेशी सहायता के ऊपर वक्तव्य देने जा रहे हैं। उन से मझे केवल एक बात पूछनी है...

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब अभी सिर्फ पेपर ले कर र हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : कागज रख रहे हैं और कागज के माने लिखा हुआ है वक्तव्य वह दे रहे हैं। जब वह कागज सदन पटल पर रख रहे हैं तो मैं उन से खाली यह पूछना चाहता हूं कि क्या कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमरीका अभी से विदेशी सहायता में एक-एक प्रतिशत अपनी राष्ट्रीय आमदनी का नहीं दे रहे हैं ? इस सवाल को पूछने का कारण यह है कि कल प्रधान मंत्री जी ने फरमाया था कि वह खुश हो जाएंगी अगर ये देश एक प्रतिशत अपनी राष्ट्रीय आमदनी का दें। मैं कहूंगा कि ये देश अभी से एक प्रतिशत दे रहे हैं।। इसलिए मैं कहूंगा कि भीख मांगने वालों को पता तो रहना चाहिये कि कितनी भीख मिल रही है उन्हें ताकि वे ज्यादा मांग सकें। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जिस पर आक्षेप की जरूरत हो। इसलिए मेहरबानी कर के आप वित्त मंत्री से इसका बिल्कुल साफ उत्तर दिलवाइये कि क्या संयुक्त राष्ट्र अमरीका और कनाडा अभी से अपनी राष्ट्रीय आमदनी का एक प्रतिशत विदेशी सहायता के रूप में दे रहे हैं या नहीं और अगर दे रहे हैं तो फिर क्या मतलब होता है कि प्रधान मंत्री जी ने फरमाया है, उसका ?

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : वह इस रूल के तहत सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। इसी रूल में लिखा हुआ है :

"When for the purposes of explanation during discussion.... on any matter then under the consideration of the House".

अभी कंसिडेशन शुरू नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : आपको अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी।

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): Sir, I would like to place before hon. Members a statement relating to my visit to Canada and the United States in the latter half of September, 1966.

My visit was occasioned by (a) the Annual Sessions of the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development which were held in Washington DC between 26th and 30th of September and (b) by the meeting of the Commonwealth Economic Consultative Council (otherwise known as the Commonwealth Finance Ministers' Conference) which is usually held on the eve of the Annual Sessions of the IMF and the IBRD . . . (*Interruption*)

Is it desired, Sir, that I should lay it on the Table?

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): It is a printed statement. Let it be laid on the Table.

Mr. Speaker: It might be laid on the Table.

Shri Sachindra Chaudhuri: Sir, I lay it on the Table. [*Placed in Library. See* No. LT-7194/66].

Mr. Speaker: Copies would be circulated to Members.

Shri Ranga (Chittoor): We can put a few questions by way of elucidation.

Mr. Speaker: After you have read it.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : क्या इस पर प्रश्न पूछने देंगे ? क्योंकि बाकी तीन वक्तव्यों के बारे में ऐसा ही हुआ है कि कोई सवाल नहीं पूछने दिया गया है । एक रेल की दुर्घटनाओं का है, उसी तरह खाद्य मंत्री का का वक्तव्य है ।

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं इस पर कहना चाहता हूं कि कल भी यह बड़े जोर से सवाल उठा था. . .

एक माननीय सदस्य : ठीक उठा था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने गलत तो नहीं कहा, इतनी बेसब्री की क्या बात है ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : बिलकल अनगंल था ।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि आपस में विरोध जरूर है क्योंकि जो रूल कहता है वह साफ है, जो कल इधर से जोर से कहा और जो मुझे याद करवाया जा रहा था कि

"No question would be put".

Shri Tyagi (Dehra Dun): "No question shall be put".

Mr. Speaker: "No question shall be put." (*Interruption*).

मेरी बात मुझे कह लेने दीजिए ।

डा० राम मनोहर लोहिया : 355 भी पढ़ लें

अध्यक्ष महोदय : 355 मैं ने पढ़ लिया । यह बात जहां तक रूल्स के लब्जों का सम्बन्ध है, बिलकुल एतराज दुरुस्त है, कि उस वक्त सवाल नहीं पूछे जा सकते जिस वक्त मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट करे गा। मगर वह 30 साल से एक कन्वेशन चली आ रही है जो मैं ने कल देखी ।

For the last 30 years it has been in practice....

An hon. Member: 35 years.

Mr. Speaker: For the last 35 years, it has been in practice.

तो इसीलिए मझे इस में दिक्कत है कि एकदम इसको इस तरह से नहीं हटाया जा सकता । मैं कांग्रेस के मेम्बर साहबान को याद दिलाना चाहता हूं . . . (**व्यवधान**) . . . . आर्डर । यह एक तरीका इसलिए शायद स्पीकर साहबान ने जो मुझ से पहले हुए उन्होंने रखा था, उन्होंने इजाजत दे दी थी

ताकि उस वक्त ही जब स्टेटमेंट हो तो क्वेश्चन हो जायें और फैसला हो जाये। वरना उस रूल के मुताबिक उस वक्त सवाल नहीं हो सकते, तो बाद में नोटिस देंगे कि हम डिस्कस करना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन फिर रखना पड़ेगा। तो फिर वही आयेगा और ज्यादा वक्त लगेगा। तो जो हाऊस चाहता हो वह दोनों बातों में तय कर लें। उस वक्त सवाल न हों, रूल का एन्फोर्समेंट कर लें, तो रिक्वेस्ट आयेगी कि इस को डिस्कस किया जाये या सवाल पूछना चाहते हैं तो फिर...

श्री क० दे० मालवीय (बस्ती) : आप जरा मेरी बात सुन लें। 30 साल से इस सदन के सामने ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई थी कि 372 कानून के अन्तर्गत हम सब लोगों में से कुछ को बाध्य हो कर यह कहना पड़े कि इसको लिटरली इम्प्लीमेंटेशन किया जाये, माना जाये इस कानून को। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आप के बहुत कहने के बावजूद, एक एक माननीय सदस्य चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों आपकी बात नहीं मानते हैं और 15-15 मिनट तक अवहेलना की जाती है। इसलिए मैं ने जरूरी समझा कि इस कानून का अक्षरशः पालन किया जाये इसके लिए आप से निवेदन करूं। और 30 वर्ष से अगर कोई कन्वेंशन ऐसी हो गई हो तो हम सब को अधिकार है यह कहने का उस कन्वेंशन को आप तोड़ दें।

श्री मधु लिमये : व्यवस्था का प्रश्न है। ..... (**व्यवधान**) मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं।

श्री राधेलाल व्यास : मेरा निवेदन है...

श्री मधु लिमये : प्वाइंट आफ आर्डर पहले सुना जायेगा या निवेदन पहले सुना जायेगा ...? प्वाइंट आफ आर्डर पहले सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने उनको बुलाया है।

श्री मधु लिमये : निवेदन पहले सुनेंगे, प्वाइंट आफ आर्डर बाद में सुनेंगे ?

श्री राधेलाल व्यास : जैसा आप ने फरमाय कि यह एक कन्वेंशन 30 साल से या 35 साल से चला आ रहा है ...

डा० राम मनोहर लोहिया : 35 साल कहां से बार-बार आ जाता है ? मैं तो समझता हूं कि खाली 19 साल से शुरू हुआ है। ... (**व्यवधान**) कुछ तो इन को सिखाइये। यह 35 साल कह कर के क्या कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा है 35 साल रेकर्ड देखकर।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप भी 19 साल कहा करिए। 35 साल खत्म करिए।

श्री राधेलाल व्यास : हम सबको ही डाक्टर लोहिया साहब यहां सिखाने के लिए मौजूद हैं और सिखाते रहेंगे और बाहर लोगों को सिखा रहे हैं, वह तो सब के सामने ही हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : सिख जाते तो यह दुर्गति न होती।

श्री राधेलाल व्यास : यह जो बात कह गई कि इतने साल से, एक लम्बे पीरिअड से यह प्रथा चली आती है, मेरा नम्रता निवेदन है कि इस पर भी विचार कर लीजिए। इसको कन्वेंशन नहीं कहते। जब कोई रूल न हो, कानून न हो, और कानून के अभाव में कोई प्रथा बन जाये, या कस्टम बन जाये, या कन्वेंशन बन जाये तो उस को कन्वेंशन

[श्री राधेलाल व्यास]

कह सकते हैं । यहां तो हमारे यहां एक नियम का उल्लंघन बराबर नियमित रूप से होता चला आ रहा है । इसलिए निवेदन है कि इस को कन्वेंशन न कहते हुए अगर यह चाहते हैं कि प्रथा यह चले, तो चाहे रूल बदल दिया जाय लेकिन रूल के होते हुए यह नहीं होना चाहिए ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अखबारों में पढ़ा कि अब की बार कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता ने . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह किस रूल के अंडर आप उठा रहे हैं ?

श्री मधु लिमये : 376, 372, और 355 इन सभी नियमों को लेकर मैं उठा रहा हूं । यह तीन तो मैंने बताये और चाहें तो और भी बता सकता हूं । तीन ले लीजिए । मैंने यह अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने इन लोगों से यह कहा कि वह कार्य-प्रक्रिया का अध्ययन कर के आयें और मैं आप के सामने यह बात रखना चाहता हूं .... (**व्यवधान**) मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस तरह से तो न दखल दीजिए । (**व्यवधान**)

मेरी बात तो सुन लीजिए । जब मैं कह रहा हूं तो वह तो सुनिए । इस तरह से 376 आप ने कह दिया और शुरू कर दिया कि मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं बन सकता ।

श्री मधु लिमये : मैंने तीन नियम बताये ।....

अध्यक्ष महोदय : 376 में ऐसा कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।. . . (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : मैंने तीन बताये हैं, 376, 372 और 355 . . .

अध्यक्ष महोदय : तो आप एक पर रिलाई करिए न , . . .

श्री मधु लिमये : तीनों संबंधित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं, यह नहीं उठ सकता है ।

श्री मधु लिमये : यह जो आप कह रहे हैं . . (**व्यवधान**)

श्री बागड़ी (हिसार) : सुने बगैर कैसे मालूम हो जायगा ? . . (**व्यवधान**)

Shri Daji (Indore): They have no faith in your capacity to deal with members....

Mr. Speaker: Then I can be asked to go out. *[Interruptions).*

क्या सवाल है इस समय जिस पर आप कह रहे हैं ? अगर इस पर कहना चाहते हैं जो इस वक्त उपस्थित है 355 का तो कहिए ।

श्री मधु लिमये : इस वक्त सवाल यह है कि क्या इन के वक्तव्य पर प्रश्न पूछ सकते हैं या नहीं और इसी के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अगर नियमों को ठीक से पढ़ा जाय तो आप 372 देखिए, वह इस प्रकार है :

"A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker, but no question shall be asked at the time the statement is made."

अगर केवल इसी नियम को लिया जाता है तो इस सदन में 15 साल से जो परम्परा बनी है उस परम्परा में और इस नियम में टकराव है, 'ऐसा मालूम पड़ता है, केवल इसी को लिया जायगा तो । लेकिन अगर साथ-साथ 355

को लिया जायगा जो अभी डाक्टर साहब ने पढ़कर सुनाया, मैं फिर से पढ़ता हूं :

"When for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason...."

ये लफ्ज याद रखिये।

"... any member has occasion to ask a question of another member on any matter then under the consideration of the House, he shall ask the question through the Speaker."

अब आप मेम्बर की व्याख्या 2 में देखें। ...(**व्यवधान**) कोई अटकाव नहीं है, आप सवाल पूछने की इजाजत दे सकते हैं। साथ-साथ मैं यह कह रहा हूं कि 372 में एक अरसे से, एक साल हो गया परिवर्तन करने के लिए मैंने संशोधन दिया था। एक साल करीब-करीब हो गया, अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। यह जो असंगति ऊपर से दिखाई देती है। परम्परा में और नियम में, 372 के अन्दर, उस को भी खत्म करने के हेतु एक साल पहले मैंने संशोधन दिया है जिस पर अभी तक नियम समिति ने कोई फैसला नहीं किया है। उस को मैं इस वक्त छोड़ देता हूं। लेकिन इस नियम के बावजूद 355 में साफ कहा है कि किसी भी सदस्य से सवाल पूछा जा सकता है। अब सदस्य की व्याख्या देखिए ...

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने पढ़ी है।

श्री मधु लिमये : सब लोगों को पता चले न ? यह सब लोग जो हल्ला कर रहे हैं, उन के लिए कह रहा हूं। आप को नहीं कह रहा हूं। मेम्बर के अन्दर सभी मेम्बर आते हैं, मंत्री भी आते हैं और गैर मंत्री भी आते हैं ....

Mr. Speaker: I would request Shri Madhu Limaye to kindly listen to me. In the defintion of a Member, which has been given, every Member is included. But when statemnts by Ministers are desrcibed then the Ministers become distinct, and those statements also become distinct at that time.

श्री मधु लिमये : लेकिन इस से मेम्बर का अधिकार तो कम नहीं होता, है उसको सदा अधिकार रहता है।

अध्यक्ष महोदय : उस वक्त

श्री मधु लिमये : हम को आपकी मारफत सवाल करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यह विरोध बराबर प्रेक्टिस में और रूल में है, इस से इन्कार नहीं किया जा सकता। 372 में जो प्रेक्टिस चली आती है, उस में जरूर विरोध है, इस में कोई शक नहीं है

डा० राम मनोहर लोहिया : आपने दुनिया भर की लोक सभायें देखी होंगी, सब जगह इस तरह से सवाल पूछा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, सब जगह होता है, लेकिन सवाल यह कि हमारे नियम क्या हैं।

श्री मधु लिमये : 355 ही वह नियम है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। कांग्रेसियों को नियम अच्छी तरह से पढ़ाइये।

Shri Nath Pai (Rajapur): While thanking you for the well-established convention of the House, which has the sanctity of a written rule, I want to join issue with what Shri K. D. Malaviya has been trying to impose on the House since yesterday. His behaviour yesterday was an example of obstruction, calculated deliberately to flout the authority of the Chair, but since in the end good sense prevailed with him and he tried to co-operate with you in maintaining order by walking out or withdrawing himself, I do not touch that. But regarding this well-established convention. I want to make this submission, in the first place about rule 389 regarding your

[Shri Nath Pai]

authority. I shall read it out for the benefit of Shri K. D. Malaviya and another Congress Member among the very few who try to read the rules, namely Shri G. N. Dixit. In spite of the admonition by the Leader, they do not look at the rules book. Rule 389 reads thus:

"All matters not satisfactorily provided for.....".

Mr. Speaker: Not specifically provided for.

Shri Nath Pai: The rule reads:

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules...."

—the words are 'detailed working of these rules'—

"....shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct.".

In the working of rule 372, as you have pointed out, a well-established convention is now available and this has the force of a written law. (*Interruption*).

I may tell my hon. friend Shri K. D. Malaviya that he does not know the ABC of the canons of interpretation.

Mr. Speaker: Order, order.

Shri Nath Pai: I am sorry I have to tell him this because he is trying to interrupt me. (*Interruption*). I do know the canons of interpretation of law.

Shri Hari Vishnu Kamath: He is a barrister.

Shri Nath Pai: A ruling which enlarges and which expands the rights, liberties and privileges of the House has the sanction of a written rule. When you cited this well established convention, if Shri K. D. Malaviya or anybody else wanted to curtail or abridge it, it was up to him to appeal to the rules of this House and not to try to obstruct and take the time of the House in the pernicious manner in which he did it yesterday.

Mr. Speaker: Order, order. Now, Shri G. N. Dixit.

Shri Nath Pai: The House should not be forced and coerced into giving up well-established conventions which have the sanctity of the rules, and I hope you will co-operate with us and uphold the convention.

Shri G. N. Dixit (Etawah): From the very preface to these rules you will find that these rules were passed by this House in March, 1957 and enforced in 1957. Therefore, what happened before 1957 has no relevance. These rules have been approved by the House and they have been made and passed by the House, and they have constitutional validity under article 118. Therefore, so far as these rules are concerned, they have the force of law.

Now, the position is this, So far as the particular rule is concerned, it is unequivocal and absolutely categorical that no question shall be asked at the time the Minister makes a statement. With all the wisdom and the totality of wisdom of this House, looking to all the pros and cons of the matter, this rule was laid down.

श्री मधु लिमये : क्या दीच की अवधि सो गये थे, क्या कुम्भकर्ण हो गये थे ।

Shri G. N. Dixit: Now, this rule can be amended not by a convention, because there is a specific provision in these rules for amendment of the rules. I will refer you to rule 331. In that rule, the manner and procedure are laid down by which a rule can be amended. This House alone is the authority which by that rule and in that manner can amend this rule. Rule 331 appears under the heading 'Rules Committee'. Rule 329 defines

the functions of the Rules Committee, rule 330 deals with how the Committee will be constituted. Then Rule 331 which says:

"The recommendations of the Committee shall be laid on the Table and within a period of seven days, beginning with the day on which they are so laid, any member may give notice of any amendment to such recommendations".

Then:

"Any notice given by a member of any amendment to the recommendations of the Committee shall stand referred to the who shall consider it and make such changes in their recommendations as the Committee may consider fit...."

And so on. The whole procedure is spelt out by which these rules can be amended. My submission is that this rule is specific, clear and categorical and no other construction can be made of that rule. So no conventions can be created to obliterate that rule.

Shri Surendranath Dwivedy: It is already there.

Shri G. N. Dixit: You, Sir, in your great experience as a Judge are fully conversant with this and know that a breach of a law cannot make that law inoperative. A breach of the law is a breach and has to be rectified.

My submission, therefore, is that if a mistake has been committed for so many years, that has to be corrected and the position restored. That is what is needed now whatever might have been done upto now.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): We have been talking about conventions. As you know, there was a well-established convention about quorum, that quorum shall not be called during the lunch hour in this House. But since it went against established law, this long-standing convention was broken. In the same way, if this convention which has been developed for the last 30 years, goes against any specific rule, that can also be given the go-by. This is the small point I wanted to make.

Mr. Speaker: Shri Maurya.

Shri Tyagi: Am I blacklisted?

श्री मौर्य (अलीगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन बीच में मुझे मत रोकना ।

अध्यक्ष महोदय: यह आप किस तरह से मुझ पर पाबन्दी लगा सकते हैं कि मैं न बोलूं, अगर इरेलेवेन्ट होगा, तो जरूर बोलना पड़ेगा ।

श्री मौर्य: बिल्कुल इरेलेवेन्ट नहीं होगा। आप जब चाहें रोक दीजियेगा ।

19 वर्षों से जो परम्परा पड़ी है, उस को दृष्टि में रखते हुए, ये अनुच्छेद 355 और 376 मेम्बर की परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ कन्फ्यूजन पैदा करते हैं । जब कन्फ्यूजन पैदा होता है तो ये रूल्ज आपको रेसीड्यूअरी पावर्स देते हैं । आप 385 को देखिये–

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct".

आपको पूरा अधिकार है कि कहां आप उसको किस रूप में टेक अप करें, या लिखित रूप में उसको रेग्यूलेट करें।

श्री त्यागी: मुझे आप से विनयपूर्वक यह कहना है कि यह जो रूल 355 है, जिस में क्वेश्चन करने की इजाजत है

[श्री त्यागी]

स्पीकर की स्वीकृति से, वह ऐसे समय पर है, जब कि डिस्कशन हो रहा हो—

When for the purposes of explanation during discussion....

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): "....or for any other sufficient reason".

श्री मधु लिमये : आगे वाला पढ़िये ।

श्री त्यागी : मैं अंग्रेजी कम जानता हूं ।

श्री मधु लिमये : फिर अंग्रेजी में बोलना छोड़ दो ।

Shri Tyagi: "When for the purposes of explanation or for any other sufficient reason....

Mr. Speaker: Order, order. Rule 355 does not prescribe any substantive thing at all. It is only a procedure, When a question is to be put by one member to another member, he can only do so through the Speaker and not otherwise. This does not give any right to ask any question. They ought to be determined independently whether the member can ask a question or not, but when a member, in the course of discussion, wants, for explanation or any other thing, to put a question to another member, then he can only address the Speaker and through the Speaker he can put the question to another member. That is all that it means, it doe not mean anything beyond that.

श्री मधु लिमये : मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं 388 के मातहत ।

Shri Tyagi: I have not finished.

इसलिये इस की वजह से 372 के माने में फर्क नहीं पड़ता । मुझे याद है कि 372 के अनुसार बहुत से मिनिस्टर्स ने अपने बयान दिये हैं और उस के बाद चेअर ने सवालों को मना भी कर दिया है । जरूरी नहीं है कि उन के बाद हमेशा सवाल कराये हों । कई बार इजाजत दे दी है और कई बार कह दिया है कि कोई सवाल नहीं होंगे । कल जो आप ने बतलाया कि यह कन्वेंशन बनाया गया है, तो अगर कोई प्रिसिडेंट ठीक है, तो मैं आप से यह रूलिंग चाहता हूं कि अगर कोई मैन्डेटरी क्लाज रूल्स में हो और उस के खिलाफ हमने कोई कन्वेन्शन यूनैनिमसली बना लिया, तो ऐसा हम कर सकते है या नहीं । जैसा मेरे दोस्त ने बतलाया कोरम के बारे में । कांस्टिट्यशन के मुताबिक कोरम जरूरी है । उसके लिए हम ने कन्वेन्शन बना लिया है कि हम इस तरह से करेंगे ।

श्री मधु लिमये : सवाल उठाया नहीं जायगा । यह कन्वेन्शन था । उठाने पर उसे रोकने की बात संविधान के बरखिलाफ होगी । लेकिन यहां नियम 355 है । आप समझते नहीं हैं ।

श्री त्यागी : लेकिन मैन्डेटरी क्लाज के खिलाफ कन्वेन्शन जो बनेगा वह उसी वक्त तक बना रहेगा जब तक हाउस यूनैनिमस है । अगर एक आदमी भी कन्वेशन को न मानना चाहे तो वह खत्म कर दिया जायगा । हम आप से रूलिंग चाहते हैं । कि हम इस तरह का कन्वेन्शन कायम कर सकते हैं या नहीं ।

Shrimati Renu Chakravartty: I am very surprised that a convention which has come into existence as a result of the growth of parliamentary practices and is not provided by the rules is now being challenged by the other members of the House I have been in the House for 15 years. I have seen Pandit Jawaharlal Nehru answering cuestions on important statements evry time, and nobody objected. Are they afraid that the Treasury Benches cannot answer our questions? (*Interruptions*). I would beg of you if they are going to take a technical position, to permit us in the Rules Committee

to categerically change this. (*Intrruptions*).

Shri Tyagi: After changing you can have it.

Shrimati Renu Chakravartty: You are afraid that the Treasury Benches cannot answer, that is why.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Centeral): I am rather disturbed to find that there is a tendency among certain members to insinuate that the Chair at any point of time has behaved so fatuously as to overside a rule in order to enforce a convention. That has never happened. The rule is there but the Chair on so many occasions, as has just been pointed out, has permitted clarificatory interrogations from the members after a statement is made. The Chair has always insisted that statements to be called for from the Minister after a statement is made should be of a clarificatory nature. The Chair has always reserved to itself the right to rule out anything which was asked by the members of a Minister after his statement was made that was not genuinely of a clarificatory nature. It is on that basis that you and your predecessors in office have consistently permitted members to ask for clarifications on items included in statements made by the Ministers of Government. If today the Congress Party is shaking in its shoes in such a fashion that it is afraid of its Ministers having to face interrogatories from the members, then we know what is what and the country also now what is what, but I resent any insinuation against the Chair that the Chair for the last 15 years has been permitting a convention which goes against the rules. It has never happened. (*Interruptions*). We adhere to the idea that this convention should be continued. That in the name of the rule being against the convention, this convention should be discarded, is something which this House will never tolerate, and you should never countenance it.

Shri Surendranath Dwivedy: Since this mater has been raised. I wish to point out that it raises another very fundamental issue, whether in all maters we shall strictly, literally, follow the rules and no conventions could be accepted in this House. Once that is made clear, you cannot prevent me here if I put my legs on the desk and sit. No rule states I should not sit like that. After all, there is a code of conduct, certain behaviour, certain procedure which we want to adopt in this House. It does not in any way go against the rules. If it goes against the rules, then it is a different matter altogether. I think, as has been rightly pointed out, because these people are in the dock and they are not prepared to face questions here, they want to raise this question.

Shri Ranga: I am certainly a stickler for these rules. We have had this rule for so long. How is it that our friends have awakened themselves to its existence now? Is it because they have begun to read these rules a new? Were not the rules there beforce? (*Interruption*) My hon. friend comes from Ujjain wherefrom the great Kalidasa hailed. It is never too late to read Kalidasa once again. (*Interruption*). My hon. friend, the Chairman, also helps you in the evening, but what I would like to say is just this. It seems that all these 370 wise men seem to have awakened themselves to the existence of this rule now. I do not know whom they want to protect. They certainly are not protecting themselves before the bar of public opinion. What does it mean? It means that, as our friends have suggested now, they have suddenly awakened themselves to this possibility of many of their amateurish Ministers not being capable of giving sensible answers, wise answers, to questions,—that is what I am holding out before them—to clarificatory questions which are admitted by the Speaker. Either they think that the Speaker is not capable of conditioning the questions, or they think that the questions are going to

[Shri Ranga]

be so very difficult and we have become so much wiser in the opposition than we have been till now and they have become so dwarfish in their own stature, in their capacity, in their intelligence and wisdom, that they are afraid of it. Why should they give this wrong impression? Is it because my hon. friend, the ex-Minister, has suddenly become a pandit of these rules, that they want to listen to him? I am only holding forth a ray of wisdom for my friends, for their consideration. I do not think it is worth their while really to persist in their opposition to the convention we have had, rightly or wrongly, a convention to which, as has been pointed out by my hon. friend, Pandit Nehru never raised any objection. On the other hand, he was too glad to answer such clarificatory questions. Shri Lal Bahadur Shastri never raised any objection. Even this new Prime Minister has not raised this objection.

श्री मधु लिमये : रंगा साहब, वह डरती हैं प्रश्नों का जवाब देने से । इन्होंने ही कांग्रेसियों को उकसाया है ।

Shri Ranga: Suddenly quite a number of these people seem to have gone into the cave of unwisdom and that is why they raise this objection. Therefore, instead of going into all these political arguments, I would like to advise my friends, on both sides not to invoke any of these things now. Iet us carry on our convention until the elections are over. When the new Parliament meets let there be a new Rules Committee, let that Rules Committee apply its mind and give its judgment.

Shri N. Sreekantan Nair (Quilon): I want to say something.

Mr. Speaker: There has been enough discussion.

Shri N. Sreekantan Nair: I have not spoken. I was trying for two days to bring to your notic a certain fact which is relevant. Why should I not be given a chance? I am only on the point that rule 372 says "at the time the statement is made". It does not say 'immediately after." So, the term 'at the time' according to me means only that the Minister should not be interrupted by asking such questions. But immediately after we are entitled, according to the rules, to ask questions.

Mr. Speaker: We have had enough; we have spent so much time. I am not going to spend any more time on this. Members need not accuse each other on that account. We must take it in the proper perspective. It is correct that this practice has been there but this also must be admitted that for sometime now right use of it is not being made . . . (*Interruptions.*)

Shri Umanath (Pudukkottai): You are in the Chair and you are permitting questions. How can it be improper?

Mr. Speaker: I must take the blame on myself also.

Shrimati Renu Chakravartty: No blame attaches to you.

Shri Umanath: Does it mean that you have been a party to the misuse of this kind? What is this? How can it be?

श्री मौर्य : सवाल पूछने दें या न पूछनेप्दें, यह ग्राप पर है . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रापको वक्त मैंने दिया है । फिर भी ग्राप खड़े हो कर बोलते चले जा रहे हैं ।

श्री मौर्य : ग्रगर दुरुपयोग हो रहा है तो यह ग्राप पर है, ग्राप सवाल पूछने दें या न पूछने दें ।

ग्रध्यक्ष महोदय : दुरुपयोग तो हो रहा है । मैं ग्राप को बन्द कर रहा हूं, ग्राप बन्द नहीं हो रहे हैं । बोलते जा रहे है ।

कल मैंने इस के बारे में कहा था । बार-बार कहा गया और श्री राधेलाल व्यास ने भी कहा था कि एमीनेंट लायर्ज हैं, उनसे राय ली जा सकती है ।

I will get it examined. I have heard all the parties now on what I should do.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): You have not heard me.

Mr. Speaker: I will decide in a day or two and then let the House know.

श्री मधु लिमये : 388 के मातहत मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव इस तरह से नहीं रख सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव रख रहा हूं । कि नियम को स्थगित किया जाए इस वक्तव्य को ले कर । पहले भी आपने कई बार इसकी इजाजत दी है । सदन केनेता को आपने कई बार इजाजत दी है (इंटरप्शन) अध्यक्ष महोदय, आपका क्या कहना है इसके बारे में ?

12.53 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FIFTIETH REPORT

The Minister of State in the department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): Sir, I beg move:

"That this House agrees with the Fifieth report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 2nd November, 1966."

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: I will place it before the House. Motion moved:

"That this House agrees with the Fiftieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 2nd November, 1966."

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): I beg to move:

"That at the end of the motion the following be added, namely:—

'subject to the modification that paragraph 3 of the said Report be omitted'."

Mr. Speaker: He should be brief.

Shri Hari Vishnu Kamath: I will be as brief as I can. Para 3 of this report is wholly *ultra vires* of the Rules of Procedure. But before I come to the main argument, may I invite your attention to the fact that this report is signed by you—"Hukam Singh, Chairman, Business Advisory Committee". There is a strange phrase in para 3, some incomprehensible phrase towards the end of that para which "recommends subject to the approval of the Speaker." I hope there is no inherent, insuperable dichotomy between you as the Speaker and you, Sir, as the Chairman of the Business Advisory Comittee. But for the fact that this document bears the weighty imprimatur of an august personage such as yourself, I would have had no hesitation in saying that para 3 is riddled with inconsistencies and contradictions which will land the House in ludicrous, prepostrous situations. But because this para bears your signature I do not want to say that; otherwise I would have said...

Mr. Speaker: After having said all that.

Shri Hem Barua (Gauhati): He has not said that.

Shri Hari Vishnu Kamath: May I come to the rule which should be read with para 3? There is a curious spent more than half an hour last "miscellaneous items of business." I epent more than half an hour last night and again this morning in a vain search for what this 'miscellane-